



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 644 राँची, रविवार, 23 श्रावण, 1938 (श०)
14 अगस्त, 2016 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

5 अगस्त, 2016

कृपया पढ़ें:-

1. आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा का पत्रांक-207 (A), दिनांक 14 जून, 2008
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- 4681, दिनांक 4 अगस्त, 2008, पत्रांक- 5575, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008, संकल्प सं०-3166, दिनांक 13 जून, 2011 एवं संकल्प सं०- 8598, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011
3. उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक- 1869/गो०, दिनांक 15 जून, 2009
4. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक- 625, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-222/2014 का०- 6756-- श्री फिलबियूस बारला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 703/03, गृह जिला- हजारीबाग) के भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर चाईबासा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-207(A), दिनांक 14 जून, 2008 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं-

आरोप सं०-1. आपके द्वारा बिना उपायुक्त के अनुमोदन एवं स्वीकृति के सदर अंचल, चाईबासा में कार्यरत राजस्व कर्मचारी एवं अमीन की प्रतिनियुक्ति खास महाल लीज नवीकरण के कार्यों के सम्पादन हेतु किया गया, जिसकी न तो अनुमति आपके द्वारा उपायुक्त से ली गई और न ही इसके अनुमोदन हेतु कोई पत्राचार किया गया। इस संदर्भ में उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर आपके द्वारा बिहार सेवा संहिता एवं बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली का संदर्भ करते हुए अमर्यादित भाषा में पत्राचार कर उपायुक्त को सुझाव देते हुए स्वयं के निर्गत आदेश को उचित करार देने की कोशिश की गई, जो आपके उदण्डता का परिचायक था। इस प्रकार का पत्राचार कर उपायुक्त को भ्रमित करने की कोशिश की गई। यह आपके स्तर के पदाधिकारी द्वारा किया गया पत्राचार कदाचार की श्रेणी में आता है।

आरोप सं०-2. आवास आवंटन संबंधी आपके द्वारा उपायुक्त, चाईबासा के समक्ष जो आवेदन प्रस्तुत किया गया वह न केवल अमर्यादित था बल्कि इससे आपके द्वारा उच्चाधिकारी के साथ पत्राचार की मर्यादा का उल्लंघन कर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा भी आपके विरुद्ध प्रतिवेदित किया गया कि उच्च पदाधिकारियों के साथ पत्राचार करने में आपके द्वारा कोई अनुशासन नहीं बरता जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस संदर्भ में आपको चेतावनी भी दी गई।

आरोप सं०-3. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा परीक्षा विधि-व्यवस्था कार्य संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति आदेश को लेने से इंकार किया गया, जो विधि-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्य की अवहेलना एवं उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है। संदर्भित विषय पर उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने पर स्पष्टीकरण का उत्तर न देते हुए विषय वस्तु से हट कर अनावश्यक पत्राचार किया गया एवं स्वयं की उपलब्धियों का बखान किया गया, जो न केवल अनुशासनहीनता का परिचायक है बल्कि इससे आपकी कार्यशैली भी परिलक्षित हुई। आपके स्पष्टीकरण को अनुचित करार दिया गया।

आरोप सं०-4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा खास महाल लीज नवीकरण/नामांतरण संबंधी अभिलेखों में प्रक्रिया का अनुपालन न कर नियम का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमोदन के लीज नवीकरण संबंधी अभिलेख सीधे अपर उपायुक्त को भेजी जाती है, जिससे न केवल स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन का मामला बनता है बल्कि इससे आपके स्वच्छंद एवं मनमाने कार्यशैली का भी प्रदर्शन होता है, जो एक सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। संदर्भित विषय पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु किए गए पत्राचार के क्रम में आपके द्वारा जिस भाषा में जबाब दिया गया ऐसी भाषा के लिए आप सक्षम नहीं हैं। उपायुक्त के द्वारा भी खास महाल लीज नामांतरण/नवीकरण संबंधी अभिलेख में नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संचिका की कार्रवाई का आदेश दिया गया परन्तु आपके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया, जो यह दर्शाता है कि आपको उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देश की कोई परवाह नहीं है।

आरोप सं०-5. कार्यालय के आवास आवंटन संबंधी अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन कर बिना उनकी अनुमति के नगर निकाय चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त प्रेक्षक को आवंटित कमरा हठ कर आपके द्वारा कब्जा किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा से अनावश्यक पत्राचार किया

गया। इस संदर्भ में स्थानीय समाचार पत्रों में भी आपके द्वारा बयानबाजी की गई, जो आपके स्तर के पदाधिकारी के लिए न तो उचित था और न ही इसके लिए आप सक्षम थे।

आरोप सं०-6. विशेष पदाधिकारी, चाईबासा के रूप में पदस्थापित कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा नगरपालिका मद से वेतन के रूप में 65,231.00 रु० का अग्रिम लिया गया था। इस संदर्भ में विशेष पदाधिकारी, चाईबासा के प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा उपायुक्त, चाईबासा को सूचित किए जाने के क्रम में उपायुक्त, चाईबासा द्वारा संदर्भित विषय पर लिए गए अग्रिम का समायोजन करने हेतु निदेशित किए जाने पर उपायुक्त के समक्ष जो पत्र आपके द्वारा प्रेषित किया गया व न केवल अशिष्ट भाषा में था, बल्कि इस प्रकार के पत्राचार के लिए आप सक्षम नहीं थे।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4681, दिनांक 4 अगस्त, 2008 द्वारा श्री बारला से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-01/स्पष्टीकरण, दिनांक 21 अगस्त, 2008 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री बारला के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5575, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 द्वारा उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, प० सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-1869/गो०, दिनांक 15 जून, 2009 द्वारा उपलब्ध कराये मंतव्य में इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया। अतः विभागीय संकल्प सं०-3166, दिनांक 13 जून, 2011 द्वारा श्री बारला के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्रीमती मृदुला सिन्हा, भा०प्र०से०, तत्कालीन सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः संकल्प सं०-8598, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्रीमती सिन्हा के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-625, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 द्वारा श्री बारला के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान निम्नवत् हैं-

आरोप सं०-1 पर बचाव-बयान- तत्कालीन उपायुक्त श्री महेश प्रसाद सिन्हा द्वारा शीघ्र निष्पादन के संबंध में कभी भी समुचित मार्ग निर्देश नहीं दिया गया और पूर्व पदस्थापित प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा लंबित अभिलेखों के निष्पादन नहीं करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब श्री बारला द्वारा त्वरित निष्पादन की कार्रवाई प्रारंभ की गई तो आरोप लगाकर प्रपत्र- 'क' गठित कर भेज दिया गया। यह कार्रवाई उपायुक्त के स्तर पर पूर्वाग्रह को परिलक्षित करता है। वृहत् पैमाने पर लीज नवीकरण अभिलेख लंबित रहने तथा राज्य सरकार को राजस्व की भारी क्षति होने के कारण एवं पत्र सं०-8/खा०म०-5-1100/82-2730, दिनांक 9 जुलाई, 1982, पत्र सं०-खा०म० विविध/95-213/रा०, दिनांक 29 जनवरी, 1996 तथा पत्र सं०-8/खा०म० नीति-8/97 (खंड-1)-644/रा०, दिनांक 15 अप्रैल, 1999 एवं श्रीमती लक्ष्मी सिंह, सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड के द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिला के राजस्व शाखा का दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 को किये गये निरीक्षण की टिप्पणी ज्ञापांक-33(बी०)रा०, दिनांक 15 जनवरी, 2003 के अनुपालन में उनके द्वारा अभिलेखों का निष्पादन लोकहित एवं राज्यहित में किया गया।

आरोप सं०-2 पर बचाव-बयान- श्री बारला का कहना है कि आरोप में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन-सा पत्राचार अमर्यादित है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर चाईबासा के रूप में अधिसूचित होने के फलस्वरूप श्री बारला द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 2008 के पूर्वाहन में प्रभार ग्रहण किया गया था। प्रभार ग्रहण के पश्चात् आवास आवंटन हेतु उनके द्वारा आवेदन पत्रांक-01/आवंटन, दिनांक 3 जनवरी, 2008 दिया गया। उपायुक्त के पत्रांक-13(बी०), दिनांक 1 जनवरी, 2008 से दण्डाधिकारी कॉलोनी स्थित सरकारी आवास सं०-01 श्री बारला को आवंटित किया गया। यह आवास उपायुक्त के आदेश से स्थापना उप समाहर्ता, प० सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापक-282(बी०)/स्था०, दिनांक 14 जून, 2006 से श्री बी० अबरार, जिला योजना पदाधिकारी, चाईबासा को आवंटित था। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना सं०-11334, दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 से श्री अबरार का स्थानांतरण जिला योजना पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर किया गया था। उक्त पद पर दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को योगदान करने की लिखित सूचना उपायुक्त, सिमडेगा को श्री अबरार के द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2008 को दी गई। चाईबासा का प्रभार इनके द्वारा दिनांक 2 जनवरी, 2008 को सौंपा गया तथा उक्त आवास को खाली करने की सूचना दिनांक 31 मार्च, 2008 को दिया गया। श्री अबरार द्वारा अनधिकृत रूप से श्री बारला को आवंटित आवास सं०-1 को अपने प्रतिस्थानी श्री श्रीनिवास को कब्जा करा दिया गया था। दिनांक 10 अप्रैल, 2008 को श्री बारला उक्त आवास में प्रवेश कर पाये। इस प्रकार श्री अबरार का उक्त आवास पर अनधिकृत कब्जा दिनांक 10 जनवरी, 2008 से 9 अप्रैल, 2008 तक रहा। उपायुक्त द्वारा तीन माह तक उक्त आवास पर रखे गये अनधिकृत कब्जा को मुक्त नहीं कराने के कारण श्री बारला द्वारा आवास में प्रवेश हेतु पत्राचार करने के लिए बाध्य किया गया। इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप निराधार है।

आरोप सं०-3 पर बचाव-बयान- श्री बारला का कहना है कि वे अपने कार्यालय में न्यायालय कार्य की कार्यवाही में व्यस्त थे, जिसमें अधिवक्ता के द्वारा वाद पर बहस की सुनवाई की जा रही थी। इसी समय लगभग 10:50 बजे पूर्वाहन में विधि-व्यवस्था प्रतिनियुक्ति आदेश प्राप्त कराने का प्रयास किया गया, जिसके कारण इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। इस तरह की महत्वपूर्ण प्रतिनियुक्ति आदेश प्रतिनियुक्ति की तिथि से काफी पहले कराया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इन्होंने वर्ष 1993 से 2008 तक के सेवा काल में विधि-व्यवस्था कार्य को सुचारू रूप से तत्परता के साथ किया है।

आरोप सं०-4 पर बचाव-बयान- श्री बारला का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता के द्वारा खास महाल के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-खा०म०/विविध/95-213/रा०, दिनांक 29 जनवरी, 1996 निर्गत है। भूमि सुधार उप समाहर्ता खास महाल पदाधिकारी घोषित है। इसी के आलोक में इनके द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर चाईबासा के रूप में खास महाल कार्यों का निष्पादन किया जा रहा था। ऐसा कोई भी आदेश/निर्देश इन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसमें उल्लेख हो कि खास महाल लीज नवीकरण संबंधी अभिलेख पर अनुमंडल पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। खास महाल पदाधिकारी के रूप में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अंचल से प्राप्त अभिलेखों को अपर उपायुक्त के पास अनुशंसित किया जाता था। अंतिम निर्णय उपायुक्त/आयुक्त एवं विभागीय स्तर से ली जाती थी।

आरोप सं०-5 पर बचाव-बयान- श्री बारला का कहना है कि तत्कालीन उपायुक्त, चाईबासा श्री एम०पी० सिन्हा के द्वारा सरकारी आवास सं०-1 को दिनांक 10 जनवरी, 2008 को आवंटित किया गया। पूर्व आवंटी पदाधिकारी श्री अबरार दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को स्थानांतरित जिला सिमडेगा में योगदान किये एवं दिनांक 2 जनवरी, 2008 को चाईबासा का प्रभार सौंपा श्री अबरार द्वारा अपने प्रतिस्थानी को आवास पर कब्जा दिलाकर तथा खाली करने की सूचना स्थापना उप समाहर्ता, चाईबासा को दिनांक 31 मार्च, 2008 को दिया गया। दिनांक 2 जनवरी, 2008 से 9 अप्रैल, 2008 तक उक्त आवास को खाली कराकर श्री बारला को आवंटित आवास का ससमय कब्जा नहीं दिलाया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर चाईबासा के पद पर श्री बारला पदस्थापित एवं कार्यरत थे। भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में ये खास महाल पदाधिकारी एवं अनुमंडल में राजस्व कार्यों के प्रधान थे। इसके बावजूद भी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-49 के तहत आदिवासी भूमि का गैर आदिवासियों को अनुमति प्रदान करने में इनके माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया। प्रक्रिया का पालन हो तथा आदिवासी रैयतों का अहित नहीं हो, इसलिए इनके द्वारा पत्राचार किया गया। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-49 के तहत आदिवासी भूमि की बंदोबस्ती में श्री बारला का मंतव्य प्राप्त नहीं करना, इनके प्रति दुर्भावना को ही इंगित करता है।

आरोप सं०-6 पर बचाव-बयान- पत्राचार में कौन सी भाषा अशिष्ट है- स्पष्ट नहीं किया गया है। आरोपी पदाधिकारी को कार्यरत अवधि का वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका (W.P.(S) No.- 5452/2008) दायर किया गया। याचिका में दिनांक 6 जनवरी, 2009 को श्री बारला के पक्ष में न्यायादेश पारित किया गया। न्यायादेश के अनुपालन में उक्त अवधि का वेतन विपत्र पारित किया गया तथा आरोपी पदाधिकारी के बैंक खाता में भुगतान किया गया। अग्रिम का समायोजन आरोपी पदाधिकारी के द्वारा इतिपूर्व कर लिया गया है।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निम्नवत् निष्कर्ष दिये गये हैं-

आरोप सं०-1 पर निष्कर्ष- श्री बारला द्वारा आरोप का कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अमीन का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति उपायुक्त की अध्यक्षता में स्थापना समिति के द्वारा किया जाता है। श्री बारला द्वारा सरकारी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करने का बताया गया कारण विधिसम्मत नहीं है। उन्हें कार्यहित में आवश्यकता होने पर उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर ही कर्मचारियों का प्रतिनियोजन करना चाहिए था। आरोप प्रमाणित हैं।

आरोप सं०-2 पर निष्कर्ष- आरोपी पदाधिकारी द्वारा कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ये समझ नहीं पाये हैं कि आरोप के साथ संलग्न साक्ष्यों के रूप में इनके पत्रों में कौन-सी भाषा अमर्यादित है। श्री बारला का पत्रांक-01/चि०प्र०, दिनांक 24 मार्च, 2008 तत्कालीन उपायुक्त श्री महेश प्रसाद सिन्हा को उनके नाम से सम्बोधित कर इनके द्वारा लिखा गया था। पत्र को पढ़ने से इसके Aggressiveness का आभास होता है तथा पत्र में शालीनता का अभाव है। इनका दूसरा पत्र पत्रांक- 256/आ०आ०, दिनांक 13 मार्च, 2008 उपायुक्त को इनके पदनाम से लिखा गया है। पत्र का

उद्देश्य सरकारी आवास उपलब्ध कराने का था। पत्र का Spirit Aggressive ही है। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा पत्रांक-216/गो०, दिनांक 26 मार्च, 2008 श्री बारला को लिखा गया था। इसमें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन्हें अपने पत्रों में अमर्यादित भाषा के प्रयोग के लिए सचेत किया गया था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा बचाव बयान में पत्रों के लेखन के समय की पृष्ठभूमि का वर्णन मात्र किया गया है। पत्रों में शालीनता के अभाव के प्रसंग में स्पष्टीकरण उनके द्वारा नहीं दिया गया है। अतः आरोप प्रमाणित है।

आरोप सं०-3 पर निष्कर्ष- आरोपी पदाधिकारी यदि न्यायालय में व्यस्त थे, तो विधि-व्यवस्था संबंधी महत्वपूर्ण प्रतिनियुक्ति आदेश अपने कर्मचारियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते थे। स्पष्टीकरा समर्पित नहीं करने के संबंध में इनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। आरोप प्रमाणित है।

आरोप सं०-4 पर निष्कर्ष- अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल का प्रधान होता है, जिसमें राजस्व मामले भी सम्मिलित हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी तथा उपायुक्त को राजस्व एवं भूमि सुधार मामलों के दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। अनुमंडल से राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी कोई भी प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से ही उपायुक्त को भेजा जाता है। इस मूल सिद्धांत की जानकारी आरोपी पदाधिकारी को नहीं होना चिंताजनक है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा से किये गये पत्राचार (पत्रांक-266/रा०, दिनांक 15 मार्च, 2008) एवं उपायुक्त, चाईबासा से किये गये पत्राचार (पत्रांक-318/रा०, दिनांक 1 अप्रैल, 2008) के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन पत्रों भाषा शालीन नहीं है। इसके संबंध में इनके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है। इनके द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में भी उत्तर नहीं दिया गया है। इनका बचाव बयान विधिसम्मत नहीं है। आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप सं०-5 पर निष्कर्ष- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा को सम्बोधित श्री बारला के पत्रांक-260/रा०, दिनांक 14 मार्च, 2008 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा द्वारा श्री बारला को प्रेषित पत्रांक-07/गो०, दिनांक 14 मार्च, 2008 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी का व्यवहार सामान्य नहीं था। इन्होंने नगर निकाय निर्वाचन की महत्ता को नजरअंदाज किया था। श्री बारला द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में की गई बयानबाजी के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। प्रेस को संवाद देने के लिए जिले में मात्र उपायुक्त ही प्राधिकृत हैं। श्री बारला भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में इसके लिए सक्षम नहीं थे। श्री बारला का बचाव बयान विधिमान्य एवं तर्कसंगत नहीं है। आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप सं०-6 पर निष्कर्ष- अनुमंडल पदाधिकारी, चाईबासा के पत्रांक-157/गो०, दिनांक 3 अप्रैल, 2008 द्वारा उपायुक्त, चाईबासा को प्रतिवेदित किया गया था कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा चाईबासा नगरपालिका में विशेष पदाधिकारी के अपने कार्यकाल (वर्ष 2004-06) के दौरान वेतन मद में नगरपालिका से 65,231/-रु० अग्रिम लिया गया था और यह राशि असमायोजित थी। इसके आलोक में उपायुक्त, प० सिंहभूम के पत्रांक-923/गो०, दिनांक 4 अप्रैल, 2008 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को उक्त राशि शीघ्र जमा करने के लिए आदेशित किया गया था। इसी आदेश की प्रतिक्रिया में आरोपी

पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-336/रा०, दिनांक 7 अप्रैल, 2008 उपायुक्त, चाईबासा को लिखा गया था। इनके पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्र की भाषा शिष्ट नहीं है। आरोप प्रमाणित होते हैं।

आरोपी पदाधिकारी श्री बारला के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री बारला के द्वारा सरकारी सेवक के रूप में अमर्यादित, अनुशासनहीन एवं गैर जिम्मेदाराना आचरण एवं कार्य किया गया है, जो कि सरकारी सेवक के आचरण के अनुकूल नहीं है।

अतः श्री बारला के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के तहत निन्दन एवं नियम-14 (iv) के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,
सरकार के उप सचिव।
